SHRI RISHI KUMAR MISHRA: Sir, will the hon. Minister assure this House that, when the terms are discussed with the Government of Iran the Government of India will not make a commitment that entire production of the Rajasthan Canal command area, or a substantial part thereof, will be pledged for supply to Iran? Reports have already appeared in the press saying that, under the terms of the agreement, the entire production of 30 lakh acres of the command area of the Rajasthan Canal, or a substaimal part thereof will be pledged for supply to Iran till the entire money is repaid. If such an agreement is made it will mean that we will be leaving out 30 lakh acres of Indian soil for agricultural production for the purposes of Iran. That would be a step detrimental to Indian interests. Will the hon. Minister give a categorical assurance that such an agreement will not be made?

MR. CHAIRMAN: This question pertains to the loan only.

SHRI RISHI KUMAR MISHRA: This question pertains to the repayment of the loan.

MR. CHAIRMAN: That is all right. You have made a suggestion.

SHRI RISHI KUMAR MISHRA: It **is** not a suggestion. Sir, it is a pointed question because the Hon. Minister has said that the terms are being discussed and will be discussed. I want him to give a categorical assurance to this House that when the terms are finalised, the Government will not make a commitment that the entire production or a substantial part of the production of the 30 lakh acres of the Rajasthan Canal command area will be pledged for supply to Iran.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, while discussing the terms and conditions, the view point expressed by the Hon. Member will be kept in mind.

श्री गणेश लाल माली : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो लोन लिया जायेगा वह कितने साल का होगा, कितने इंस्टालेशंस के अन्दर आयल सप्लाई किया जायगा कितने .इंस्टालमेंट में गेहूं देना पड़ेगा, आयल और गेहूं के रेट्स क्या होंगे और जो आयल दिया जायगा उस पर जो मनी बनेगी उस मनी पर कितना इंटरेस्ट दिया जायगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, अभी यह ब्योरे की बातें तय नहीं हुई हैं, इनके बारे में भविष्य.में बातें होंगी ।

*244. *[The questioner (Shri F. M. Khan) was absent. For answer* vide Col. *infra.]*

Legislation to Provide Basic Necessities to Workers

245. SHRI MAHENDRA BAHADUR SINGH: SHRI SAWAISINGH SISODIA:† SHRI SAT PAUL MITTAL; SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH: SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring forward a Bill before the Parliament to provide basic necessities like food, shelter, clothing and medical aid to the labourers working out side their home states; and

(b) if so, what are the details in this rgeard?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साई) : (क) और (ख) अनुमानत: संकेत दादन श्रमिकों की ओर है, जिन्हें उड़ीसा राज्य के बाहर स्थित निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए आमतौर पर उड़ीसा से भर्ती किया जाता

†The question was actually asked on ;he floor of the House by **Shri** Sawaisingh Sisodia.

है । उड़ीसा के दादन श्रमिकों के प्रश्न की जांच करने तथा इस प्रणाली के दुरुपयोगों को समाप्त करने हेतु उपाय सुझाने के लिए जो ठोस समिति कुछ समय पूर्व नियुक्त की गई थी, उसने इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के संबंध में उपयुक्त कानून की सिफारिश की है । राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह लेते हुए इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY 'OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) and (b) Presumably reference is t_0 Dadan Labour, who are usually recruited from Orissa for work to construction projects located outside the State (OriSsa). The Compact Committee appointed sometime ago to go into the question of Dadan Labour of Orissa and to suggest measures for eliminating abuses of this system, has recom-mended suitable legislation for such inter-State migrant workers. The matter is being examined in consultation with the State Governments and other interests concerned.]

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय मंत्री जी ने जिन अनुमानों और संकेतों का अंदाजा लगाया है वह पूरे ठीक नहीं हैं । ये आम तौर पर दूसरे सभी मजदूरों के लिए हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया है कि जो आम आवश्यकताएं मजदूरों की हैं उनकी पूरी व्यवस्था की जायगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो मकान, खाद्यान्न और कपड़ा आदि की व्यवस्थाएं हैं—उन मजदूरों की बात तो बहुत दूर है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं—क्या ये व्यवस्थाएं उन मजदूरों के लिए पूरी हो गयी हैं जो पब्लिक सेक्टर की फैक्टरीज में काम करते हैं ? क्या उन मज-दूरों के लिए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं करने के बारे में क्या आपने इस साल की अवधि में सोचा है और इन व्यवस्थाओं को आप किस प्रकार से पूरा करना चाहते हैं ?

श्री लारंग सई : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि हम सारे मजदूरों को कानून की दृष्टि से और कानून के आधार पर सहूलियतें दें । ऐसी शायद उनकी मंशा है । मैं यह कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि यह तो संभव नहीं है लेकिन उन मजदूरों की, जिनकी इस देश में काफी बुरी स्थिति है, इनमें इमिग्रांट लेबर्स भी आते हैं, स्थिति को सुधारने के लिए पिछली बार जो सभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी तो उसमें तदर्थ लेबर के बारे में तय किया गया था कि एक कमेटी बनाकर इनकी समस्याओं की छानबीन की जाय तथा इसके लिए कानून बनाये जांय । इस संबंध में एक कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है परन्तु चूंकि इससे कई राज्य संबंधित हैं और इन सबसे सलाह करनी है अतः हम इनकी सलाह आ जाने के बाद निश्चित रूप से इसके बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मंत्री जी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है । क्या आप उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखेंगे और उन कमेटी ने जो मोटे-मोटे सुझाव दिए हैं उनको बतलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री लारंग सई : श्रीमन् अभी तो केवल कमेटी की रिपोर्ट आई है । अभी तो हम प्रत्येक राज्य से उनकी राय मंगा रहे हैं और उनके सुझाव अभी आए हैं और इसके बाद भी अन्य राज्यों से कई प्रकार के सुझाव आएंगे । इसलिए श्रीमन्, मैं आवश्यक नहीं समझता हूं कि अभी उसको सभा-पटल पर रखा जाए ।

SHRIMATI HAMIDA HABIBUL-LAH: Sir, considering that heartless exploitatipn of contract worker* by unscrupulous employers is a

crying scandal and nothing is being done to ameliorate their plight, may 2 ask the hon. Minister whether he will take full measure of the problem and first try to ensure that the States implement the Act vigorously? After all, nothing prevents them from confiscating the licence of errant contractors and penalising the employers who fail to register themselves.

श्री लारंग सई : सभापति महोदय माननीय सदस्या ने जो यह पूछा है कि इसके बारे में जानकारी है या नहीं, तो श्रीमान्, "घायल की गति घायल जाने श्रौर न जाने कोये" । तो थोड़ा-बहुत मैं भी जानता हूं क्योंकि श्रीमन्, मैं तो उन मजदूरों के बीच में रहा हूं जहां इस प्रकार बदलने की स्थिति है—दूसरे राज्यों में ले जाए जाते हैं श्रौर निश्चित रूप से श्रभी तक कोई ठोस काम नहीं हो सका था इसीलिए हम इसके लिए ठोस कदम उठा रहे हैं श्रौर उनका जो शोषण होता है, उनको समय पर मजदूरी नहीं मिलती, दवाश्रों की सुविधा नहीं होती, रहने का ठिकाना नहीं होता, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं इसलिए हम राज्यों में भी सलाह मशवियरा चाहेंगे ।

SHRI PRAKASH MEHROTRA; Sir, the Fifteenth Labour Conference had recommended a minimum need-based wage. I want to ask the hon. Minister when Government will take steps to ensure that all the workers get the need-based minimum wage so that their needs of food, shelter a^n^d clothing are covered.

श्री लारंग सई : सभापति महोदय, यह दादन लेबर के संबंध में नहीं है । यह वेजेज के बारे में है । वह प्रश्न श्रागे जा रहा है । उस समय माननीय सदस्य इसके बारे में पूछ सकते हैं ।

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, we we have been raising this point in this ^House because there has been flagrant exploitation of the labour, mainly from Orissa, and I am thankful that this Government is paying due attention to the problem. May I know, Sir... *(Interruptions)* Not at all.

MR. CHAIRMAN; Mr. Misra, do not try to argue with him.

SHRI LOKANATH MISRA: May I know whether the Government is making an attempt to ensure that at least the minimum wages are paid to the workers by the public sector undertakings as well as the private employers? And what arrangement is being made for recruitment of Dadan labourers and to see that the contractors or intermediaries do not exploit the labour from Orissa particularly and also from other States?

SHRI RAVINDRA VARMA; Sir, as my colleague said, we are concerned with the various aspects of this question and the committee has submitted a report which has suggested that a special law should be passed in respect of the migrant labour recruited from Orissa and elsewhere. All the points that my hon. friend, Mr. Misra, referred t_0 the subject-matter $_0$f the suggestions that have been made. As far as payment of wages and the measures necessary to ensure that daily wages are paid to the workers are concerned, as far as the method of recruitment is concerned, as far as the as far as the housing conditions in which these labourers have to live are concerned, i_n respect o* all these matters as well as the enforcement of the different laws that apply to such Labour, the law under consideration will have provision.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र: श्रीमन्, श्रभी हाल ही में श्रम राज्य मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्दी ही एक बड़ा कंप्रेहंसेव लेबर लाज के संबंध में बिल सरकार लाने वाली है ।तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह मुद्दे जैसे शेल्टर, हाउसिग श्रादि के उसमें

रहेंगे श्रौर उसमें इन का प्रावधान किया जायेगा या नहीं ?

SHRI RAVINDRA VARMA: These are two different questions, One 13 about the general problems of workers and their amenities like housing, shelter, etc. and in this case it is not possible to legislate for citizens of one State living in another State; it will lead to the question of discrimination. As far as the other question—the general question of a comprehensive legislation—i_s concerned, if has been stated in this House and I would like to avail myself of this opportunity to state again that it is the intention of the Government to bring forward this legislation during this Session and to try to get it passed during this Session.

SHRI G. LAKSHMANAN; I would like the honourable Minister—leave aside the question of providing food, shelter, clothing, etc.—to visit Bombay and see how the Tamil Labourers are living there so that he would know whether those labourers are animals or human beings. Can the honourable Minister assure us that the labour from one part of India working in another part of India are provided with minimum hygienic conditions? If the Government cannot provide them, why cannot they force the capitalists and vested interests who are extracting their labour, to give them accommodation, at least small huts with hygienic conditions? The conditions are very bad

MR. CHAIRMAN: This h_e has tried to explain.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOW-DHURY; The conditions are very bad particularly in Tamil Nadu.

SHRI G. LAKSHMANAN; No, it is only in the northern part of India.

SHRI RAVINDRA VARMA; I have gone to Bombay before and I shall go to Bombay again, but a visit to not necessary for the specific purpose of realising whether the workers from Tamil Nadu are human beings or otherwise. They are human beings. I have no doubt at all, and they would, therefore, receive all the attention that the workers i_n the State a_s well as in the whole country receive.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shyam Lai Yadav. Please be breief.

श्री श्याम लाल यादव : मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग यह समझते हैं कि यह उड़ीसा के लेबर के साथ ही होता है वह भ्रम में हैं। उड़ीसा ही नहीं हर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जा कर काम करते हैं, खास कर गरीब लोग, श्रौर वह दो तरह के लोग हैं। एक तो इंडस्ट्रियल लेबर है, लेकिन बहुत से लोग जो गांवों में छोटे मोटे रोजगार में लगे हैं खास तौर से ईंट भट्टे की मजदूरी में, वह उत्तर प्रदेश में श्रौर दूसरे प्रदेशों में लगे रहते हैं, बल्कि दिल्ली में तो उन का एक बहुत बड़ा श्रान्दोलन चल रहा है श्रौर उस के लिये सत्याग्रह भी हुश्रा था। श्रन्त में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी जिस से यह स्पष्ट हो सके कि कमेटी ने क्या सिफारिश की। गवर्नमेंट कोई फैसला कर ले श्रौर तब कमेटी की रिपोर्ट छपे उस से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हम लोग उस पर कोई राय नहीं दे सकते। तो क्या यह मुनासिब नहीं है कि जो लोग बराबर मांग करते रहे हैं कि रिपोर्ट पेश की जाय, जब उन के हाथ में सत्ता श्रायी तो फिर उस पर कुंडली मार क्यों कर बैठ रहे है ?

SHRI RAVINDRA VARMA; The first part of his question, I would like to submit humbly, does not arise from the main question. As far as the other part is concerned, the Government does not suffer from any allergy in placing any relevant document on the Table of the House. Thi« is the report of a committee $_0$f officials^—a compact committee—and this report has been presented for exam-

nation. And it has to be examined not only by the Labour Ministry at the Centre but all the States concerned because this is a question of migrant labour, the labour recruited from one State and employed in another State. So the State where the recruitment takes place as well as the State where the deployment takes place, the kind of action required on the part of both the States, etc. are involved in this report. Therefore, it is necessary for us to elicit the opinions of the States and get them examined because the report is the basis for some proposal for legislation and it will affect the States concerned. And we have proposals in this Bill which would mean giving the right to the workers to prefer appeals against infringement of laws in the different States concerned. All these are matters where we need the opinion of different States and that is why my distinguished colleague said that we do not think at this stage we can put it on the Table of the House.

श्री रामानन्द यादव : सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस के लिये एक कंप्रेहेंसिव बिल लाया जायगा । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसा बिल बनाने के समय जो मीनिमम वेजज सरकारी प्रतिष्ठानों में कंट्रेक्टरों द्वारा दिये जाते हैं वह बहुत ही कम हैं ।

सभापति जी, हमारे स्टील मिनिस्टर बोकारो गये थ और एक महिला और एक छोटा सा बच्चा उनसे मिला और उनको बताया कि हमको उन लोगों से 3 रुपया और डेढ़ रुपया प्रतिदिन मिलता है । उनकी आंखों में आंसू आने लग गये थे । इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के प्रतिष्ठानों में जहां कांट्रेक्टर्स ने डेली वेजेज पर लेबर को बहाल कर रखा है, वह कम से कम जो मीनिमम वेजेज तय किया गया है, भारत सरकार द्वारा वह देंगे ? अगर भारत सरकार ने मीनिमम वेज तय नहीं किया है तो सरकार जो कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाने जा रही है उसमें मीनिमम वेजेज 8 रुपया प्रति व्यस्क और 6 रुपया प्रति बच्चे के आधार पर तय करेगी ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir I am afraid there is a ^little confusion as far as the Industrial Relations Bill is concerned. That governs the industrial relations and not the minimum wages. There are separate Act* to govern the minimum wages and it is the attempt of the Government to enforce these Acts in every respect.

As far as the Minister of Steel's visit is concerned, it is a compliment that the tears could move even a man of steel.

Wages and for Agricultural Labour

*246. SHRI RISHI KUMAR MISH-RA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) what were the prevailing rates of wages for the agricultural labour in each State during the year 1977;

(b) what is the number of states where the prevailing rates are less than the minimum wages prescribed under the Minimum Wages Act; and

(c) what steps Government propose to take to ensure payment of minimum wages at the rates stipulated under the law to the agricultural labour in the States were such labour is paid at lesser rates?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). Statement I showing minimum wages in agriculture prescribed under the Minimum Wages Act and statement-II indicating available information relating to daily wage rates (of annual averages) of plough-man or field labour-man in different Statet during the years 1974-75 to 1976-77^ are placed on the Table of the Houie.